

सर्वोच्च स्तर पर रक्षा निर्यात : मंत्रालय

▶ 2029 तक 50,000 करोड़ रक्षा निर्यात का लक्ष्य
▶ 38424 करोड़ के सामग्रियां बेची गईं

नई दिल्ली, 02 अप्रैल. भारत ने अपने रक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है. वित्त वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62.66 प्रतिशत अधिक है.

रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार एक वक्तव्य में कहा कि यह राशि पिछले वित्त वर्ष के 23,622 करोड़ रुपये के आंकड़े से 14,802 करोड़ रुपये (62.66 प्रतिशत) अधिक है. इस



ऐतिहासिक उपलब्धि में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों और निजी क्षेत्र का योगदान क्रमशः 54.84 प्रतिशत और 45.16 प्रतिशत रहा है. इस सफलता में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों का

योगदान रहा, जिसमें डिफेंस पीएसयू की हिस्सेदारी 54.84 और निजी क्षेत्र की 45.16 प्रतिशत रही. भारत अब अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया समेत 100 से अधिक देशों को सैन्य उपकरण

निर्यात कर रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान और रक्षा नीतियों ने पिछले 10 साल में उत्पादन और निर्यात में नई ऊँचाइयाँ हासिल करने में मदद की है.

11 केवी लाइन मानक से नीचे मिलने पर जेई निलंबित

लखनऊ/गाजीपुर 02 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर विद्युत उपकेंद्र महारौर के अवर अभियंता (जेई) धर्मद पाल को विभागीय उत्तरदायित्व के निर्वहन में लापरवाही के आरोप में देर रात निलंबित कर दिया गया है.

इसके साथ ही अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड जंगीपुर, गाजीपुर प्रवीण कुमार तिवारी को भी आरोप पत्र निर्गत किया गया है। दरअसल, एक दिन पूर्व बलिया जाते समय विद्युत वितरण मंडल गाजीपुर के अंतर्गत विद्युत वितरण खंड जंगीपुर के क्षेत्र में महारौर से रसड़ा मार्ग पर

निरिक्षण के दौरान 11 केवी विद्युत लाइन मानक से अधिक नीचे पाई गई। इस गंभीर लापरवाही को सजा में लेते हुए उनके द्वारा तत्काल संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए थे। मंत्री ए.के. शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि विद्युत व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही, विशेषकर सुरक्षा मानकों से जुड़ी अनदेखी, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी विद्युत लाइनों का मानकों के अनुरूप रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, जिससे आम जनता की सुरक्षा के साथ-साथ निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनी रहे.

मंत्रालय में सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक 10,000 एंटी कॉर्ड गायब

मुंबई. मुंबई स्थित मंत्रालय में डीजी ऐप के जरिए जारी किये गये लगभग 10,000 एंटी कॉर्ड गायब होने का खुलासा होने से राज्य के प्रशासनिक मुख्यालय में प्रवेश नियंत्रण की गंभीर चूक सामने आयी है। यह मामला अधिकारियों के लिए एक बड़ी परिचालन चुनौती बन गया है, खासकर इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में आगंतुक अपना काम पूरा करने के बाद कॉर्ड वापस करना भूल गए हैं. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस समस्या की गंभीरता तब स्पष्ट हुई जब रिपोर्ट से पता चला कि हजारों आगंतुक अपना एक्सेस कॉर्ड जमा किये बिना ही परिसर से बाहर चले गये.

उत्तराखंड पुलिस का सम्मान ऐतिहासिक उपलब्धि : धामी

▶ राष्ट्रपति पुलिस कलर से अलंकृत होने पर मुख्यमंत्री ने जताया गर्व
▶ उत्तराखंड पुलिस को मिला सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान

देहरादून 02 अप्रैल. उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर से अलंकृत किया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आईपीएस दीपम सेठ द्वारा गुरुवार को इसकी जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई जिसपर उन्होंने प्रशंसा व्यक्त करते हुए इसे राज्य के इतिहास का स्वर्णिम एवं गौरवपूर्ण अध्याय बताया. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह क्षण केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि गौरव, परंपरा और अदम्य सेवा भावना का जीवंत



प्रमाण बनकर सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस को देश के उन चुनिंदा पुलिस बलों की श्रेणी में स्थापित करता है. जिन्हें उनकी विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए यह सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई है। उन्होंने भी धामी के साथ ही अधिकारियों और जवानों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं.

बीमार का इलाज सरकार की प्राथमिकता : योगी

▶ हर जरूरतमंदों को मिलेगा आवास



गोरखपुर, 2 अप्रैल. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 100 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं.

इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को आवास और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के इलाज के लिए हर संभव आर्थिक सहायता देने का भरोसा दिलाया. जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने बैठे लोगों के बीच पहुंचकर एक-एक कर उनकी

समस्याएं सुनीं. उन्होंने प्रार्थना पत्र लेकर संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी मामलों का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतुष्टिपरक तरीके से किया जाए. पुलिस से जुड़े मामलों में त्वरित और सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए.

एआई से बांझपन के उपचार की पहल

नई दिल्ली. फर्टिलिटी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) आधारित बांझपन उपचार की की नयी पहल की गयी है। यह पहल अग्रणी गौडियम आईवीएफ ने की है. इस नयी तकनीक के तहत एआई-आधारित एम्ब्रियोलांजी सिस्टम को नियमित उपचार प्रक्रिया में शामिल किया गया है. एम्ब्रियो के चयन को अधिक सटीक और डेटा-आधारित बनाने में मदद मिलती है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस पहल का उद्घाटन किया. एआई जैसी तकनीकों को अपनाता भारत की नवाचार क्षमता को दर्शाता है और भविष्य में विभिन्न क्षेत्रों में तकनीक आधारित समाधान मजबूत करेगा. यह तकनीकी इंटीग्रेशन आईवीएफ 2.0 के साथ साझेदारी में किया

आज का इतिहास

1325 - चिरती सम्प्रदाय के चौथे संत निजामुद्दीन औलिया का निधन.
1680 - मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का निधन.
1903 - समाजसुधारक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भारतीय हस्तकला के क्षेत्र में नवजागरण लाने वाली गांधीवादी महिला कमलादेवी चट्टोपाध्याय का जन्म.
1914 - भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष सैमन केशव का जन्म.
1942 - जापान ने द्वितीय विश्वयुद्ध में अमरीका पर आखिरी दौर की सैन्य कार्यवाई शुरू की.

71 लाख आवेदकों को 21,300 करोड़ वितरित

डाटा सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया में गंभीर खामियां सामने आईं

मुंबई, 02 अप्रैल. राज्य सरकार की %मुख्यमंत्री माझी लाइकी बहिन% योजना बड़े विवाद की ओर बढ़ रही है। इस पहल की शुरुआत फॉर्म भरें और लाभ पाएं के दृष्टिकोण के साथ की गयी थी, ताकि अधिक से अधिक महिलाओं तक पहुंचा जा सके. लेकिन हाल के डाटा सत्यापन और ई-केवाईसी प्रक्रिया में गंभीर खामियां सामने आयी हैं। हाल के निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि लगभग 71 लाख महिलाएं इस योजना के लिए अयोग्य पायी गयी हैं। इसके बावजूद, राज्य सरकार पिछले 20 महीनों में उनके खातों में लगभग 21,300 करोड़ रुपये जमा कर चुकी है.

इन अयोग्य उम्मीदवारों को बाहर कर सरकार को भविष्य में हर महीने लगभग 1,065 करोड़ रुपये की बचत होने की उम्मीद है। जांच में खुलासा हुआ कि कई लाभार्थी अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करते थे। अयोग्य घोषित किए जाने के मुख्य कारणों में शामिल हैं-परिवार की आय 2.5 लाख रुपये की सीमा से अधिक होना, परिवार के सदस्यों का सरकारी नौकरी में होना, परिवार में चार पहिया वाहन का होना और प्रारंभिक आवेदन चरण के दौरान विकल्पों का गलत चयन.

सरकार ने स्वीकार किया है कि कई वास्तविक लाभार्थियों को तकनीकी दिक्कतों और प्रारंभिक आपदाओं का सामना करना पड़ा है, जिससे वे अपना सत्यापन पूरा नहीं कर पाये। नतीजतन ई-केवाईसी की समय सीमा 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ा दी गयी है। मई 2026 से उन लोगों के लिए 1,500 रुपये का मासिक भुगतान स्थायी रूप से बंद कर दिया जायेगा जो अयोग्य पाये गये हैं या अपना ई-केवाईसी पूरा करने में विफल रहे हैं। उनके नाम भी सिस्टम से अस्थायी रूप से निलंबित कर दिये जायेंगे.



भजनलाल ने माय भारत पोर्टल के तहत ली बैठक जयपुर. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को यहाँ माय भारत पोर्टल के तहत प्रदेश में की जा रही गतिविधियों को लेकर बैठक ली. मुख्यमंत्री निवास पर हुई इस बैठक के दौरान श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि युवा शक्ति को लाभान्वित करने के लिए इस पोर्टल के तहत अधिक से अधिक गतिविधियां आयोजित की जाएं. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद थे.

गोलीबारी की घटना में पूर्व सैनिक गिरफ्तार, एक की मौत

मुंबई, 02 अप्रैल. महाराष्ट्र में ठाणे जिले के मुंजा क्षेत्र में एक पूर्व सेना कर्मी को व्यक्तिगत विवाद के चलते गोलीबारी कर एक व्यक्ति की हत्या और दो अन्य को गायब करने के आरोप में गिरफ्तार किया

गया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी 51 वर्षीय जयन शिवानंदन नायर ने गुरुवार सुबह करीब 11-30 बजे कैलाश नगर इलाके के पास मुंजा बाईपास पर कुछ लोगों पर गोली चला दी। इस घटना में

अकबर अब्दुल शेख (29) की मौत हो गई, जबकि अब्दुल हसन शेख (45) और समीर अहमद शेख (32) गंभीर रूप से घायल हो गए। तीनों घायलों को तत्काल एक निजी अस्पताल ले जाया गया,

जहां अकबर को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि अन्य दो का इलाज जारी है। घटना आरोपी को पालित बहन के साथ कथित उत्पीड़न को लेकर चल रहे विवाद का परिणाम थी.

गैंगस्टर आरोपी की 93 लाख की संपत्ति कुर्क

बुलंदशहर. उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में संगठित अपराध में शामिल एक गैंगस्टर आरोपी की लगभग 93 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क करने का आदेश न्यायालय ने पारित किया है. विशेष लोक अभियोजक (गैंगस्टर एक्ट) योगेश कुमार के अनुसार, स्थाना तहसील के ग्राम हकरोली, थाना खानपुर निवासी अभियुक्त पुषेंद्र पुत्र दीनदयाल पर आरोप है कि उसने अवैध धन अर्जित करने के लिए एक सक्रिय गिरोह बना रखा था. वह क्षेत्र में जुआ और सट्टा खिलाकर अवैध रूप से धन एकत्र करता था. पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की.

लोकप्रियता से घबराकर हो रही कार्रवाई

▶ 160 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए: केजरीवाल

नई दिल्ली/अहमदाबाद, 02 अप्रैल. आम आदमी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया जा रहा है.



केजरीवाल ने दावा किया कि पिछले तीन महीनों में 160 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है, जो राजनीतिक दमन का संकेत है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनाव

कोशिश की जा रही है. पत्र में उन्होंने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर भाजपा इस तरह की कार्रवाई कर रही है. केजरीवाल ने विशेष रूप से आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी की गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए इसे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक बताया.

केरल में बदलाव की लहर : पीएम मोदी

▶ कार्यकर्ताओं ने संवाद में भाजपा पर जताया भरोसा
▶ लोग भाजपा-एनडीए की ओर देख रहे हैं



नई दिल्ली/तिरुवनंतपुरम, 02 अप्रैल. नरेंद्र मोदी ने केरल के पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर अपनी बात रखी. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अनुभव साझा करते हुए एलडीएफ और यूडीएफ पर निशाना साधा.

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों गठबंधनों के वर्षों के कुशासन ने केरल के विकास को प्रभावित किया है और राज्य को पीछे धकेला है. उन्होंने यह भी कहा कि अब राज्य के लोग बदलाव चाहते हैं और

भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस पर साधा निशाना

नई दिल्ली. भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा बंधक बनाने की निंदा करते हुए कहा कि राज्य में जंगलराज कायम है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भाजपा मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को देखते हुए ममता बनर्जी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि मालदा जिले में गहन विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के दौरान सात न्यायिक अधिकारियों को तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घेरकर बंधक बना लिया, जिनमें तीन महिला न्यायाधीश भी शामिल थीं। यह घटना राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े करती है। श्री भाटिया ने कहा कि ये अधिकांश शीर्ष न्यायालय के निर्देशों के तहत अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन उन्हें घंटों तक रोके रखा गया। उन्होंने दावा किया कि देर रात

करीब बारह-एक बजे अधिकारियों को मुक्त कराया गया और जाते समय उनकी गाड़ियों पर पथराव भी किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह घटना न्यायिक अधिकारियों को डराने और एसआईआर प्रक्रिया में बाधा डालने की सुनियोजित साजिश का हिस्सा है। पश्चिम बंगाल में जंगलराज की स्थिति बन चुकी है, जहां अधिकारी भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने मामले को गंभीरता को देखते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को राज्य के पुलिस महानिदेशक से हस्तक्षेप करने के लिए कहना पड़ा, ताकि अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भाटिया ने दावा किया कि शीर्ष न्यायालय को इस मामले में राज्य सरकार को फटकार लगाई है और आवश्यक निर्देश दिए हैं। भाजपा ने इस घटना को लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के शासन पर गंभीर हमला बताते हुए राज्य सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग की है.

बैठक ▶ कृषि मंत्री चौहान ने कहा तकनीक के माध्यम से हर किसान तक खाद पहुंचाएं

आईडी से योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा

नई दिल्ली, 2 अप्रैल. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक में स्पष्ट संदेश दिया कि एक ओर हर किसान तक सरकारी योजनाओं, एमएसपी खरीद और पीएम-किसान जैसी डीबीटी आधारित सहायता पहुंचाने के लिए डिजिटल फार्मर आईडी को तेजी से सार्वभौमिक बनाना है.

तो दूसरी ओर देश में उपलब्ध पर्याप्त उर्वरक स्टॉक का वितरण इस तरह सुनिश्चित करना है कि न किसी किसान को कमी महसूस हो, न कहीं जमाखोरी और कालाबाजारी के लिए कोई गुंजाइश बचे। उन्होंने कहा कि किसान को एक फार्मर आईडी के माध्यम से उसकी जमीन, फसल और जरूरत के अनुरूप ही खाद व अन्य सब्सिडी उपलब्ध कराई जाए,

हर किसान तक सीधा लाभ

बैठक का उद्देश्य- हर किसान तक सीधा लाभ-बैठक में पहले सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ फार्मर आईडी को केंद्र में रखकर चर्चा की गई, ताकि डीबीटी, एमएसपी पर खरीद, उर्वरक सब्सिडी, फसल बीमा और अन्य योजनाओं का लाभ सीधे किसान के खाते में पहुंचे. केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि फार्मर आईडी को भारत की डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर एक ही प्लेटफॉर्म पर किसान की पहचान, जमीन, फसल और योजनाओं का पूरा प्रोफाइल उपलब्ध कराया जाएगा.



पश्चिम बंगाल में फिर हिंसा, पुलिस भी निशाने पर बीरभूम. पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में गुरुवार को दो गुटों के बीच हो रही हिंसक झड़प को रोकने की कोशिश में सूरी सदर थाना प्रभारी (आईसी) सहित कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. यह विवाद कंकुरिया गांव में सड़क निर्माण को लेकर ग्रामीणों के दो समूहों के बीच शुरू हुआ था, जिसने अंततः पथराव का उग्र रूप ले लिया. स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले भी विवादित जमीन पर निर्माण कार्य को रोका था, लेकिन ठेकेदार और मजदूर जैसीबी मशीनों के साथ जबरन काम शुरू करने पहुंच गए. घटना की सूचना मिलते ही जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो भीड़ ने उन्हें निशाना बनाना शुरू कर दिया. पथराव में सूरी सदर थाने के निरीक्षक शैलेंद्र उपाध्याय के सिर में गंभीर चोट आई है.

राज्य को एटीएम बना दिया है: राहुल

नई दिल्ली. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने असम विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार अभियान में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार देते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री करार दिया और यह भी कि राज्य में नफरत और डर का माहौल बनाया जा रहा है, जबकि असम की पहचान आपसी भाईचारे और सांस्कृतिक एकता से रही है. उन्होंने महान हस्तियों की विरासत का उल्लेख करते हुए लोगों को जोड़ने और प्रेम का संदेश आगे बढ़ाने की बात कही. श्री गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुहमंती अमित शाह और असम सरकार ने राज्य को एटीएम बना दिया है. राज्य की जमीन बड़े उद्योगपतियों को दी जा रही है और इसके बदले राजनीतिक लाभ लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह सरासर भ्रष्टाचार है. गौरतलब है कि गुरुवार को श्री गांधी ने असम के परीहजन और जोरहाट विधानसभा में जनसभाओं को संबोधित किया.

